(d) The following amenities are provided to oustees on their rehabilitation:—

(i) A living hut or temporary accommodation is provided.

(ii) A house building loan of Rs. 2,000 per family is allowed.

(iii) Pucca drinking water diggies are provided in the resettlement chaks.

(iv) Dispensaries, Schools, link roads etc. are provided in the new abadies, where considered necessary.

(v) other facilities made available are the taccavi loan for purchase of camel|bullocks, good quality seeds, assistance in getting tractors on hire.

**दिल्ली में मल-वहन (सीवेज) व्यवस्था**

394. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली की यमुना पार की बस्तियों में मलवहन की व्यवस्था (सीवेज सिस्टम) बनाने के लिये दिल्ली नगर निगम की कोई योजना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) :** (क) जी हां ।

(ख) (1) 0.49 लाख रुपये की अनुमानित लागत की शाहदरा सलेल योजना (पहला भाग) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन द्वारा मंजूर कर दी गई है ।

(2) शाहदरा के कुछ भाग में ट्रंक सीवर्स की व्यवस्था करने के लिए 304.95 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक मलवहन (सीवरेज) योजना की केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन तकनीकी छानबीन कर रहा है ।

**दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाट**

395. **श्री हर दयाल देवगुण :** क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने 1962 से लेकर अब तक कितनी भूमि का अर्जन किया ;

(ख) इस भूमि का विकास करने के बाद कितने प्लाटों को नीलाम किया अथवा बेचा;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्य की गति कुछ धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो कार्य की गति तीव्र करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) 8,040 एकड़ ।

(ख) 30 अप्रैल , 1967 तक 4,361 रिहायशी तथा 593 औद्योगिक प्लाट ।

(ग) जी हां । भूमि-विकास की प्रगति में प्रमुख गतिरोध हैं :—

(i) पानी की सप्लाई तथा ट्रंक सर्विसज में देरी,

(ii) कुछ प्लाटों के कब्जों के सम्बन्ध में न्यायालय आदेश (कोर्ट इन्जैक्शन) ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से कहा गया है कि जहां सम्भव हो वहां पानी की